जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 240 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 3 जुलाई, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गांधी की ''कोर टीम'' के सदस्य अधिकतर पी.डब्ल्यु.डी मिनिस्टर हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में

हरीश चौधरी, गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री थे, विजय सिंगला पी.डब्ल्यु.डी मंत्री थे पंजाब की कांग्रेस सरकार में, बायरागौड़ा कर्नाटक में पी.डब्ल्यु.डी. मंत्री हैं आदि, आदि

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जुलाई। राहुल गांधी की कोर टीम में ऐसे पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें उनकी सादगी और झोला छवि के आधार पर चुना गया है।

वे जूते नहीं, बल्कि चप्पल पहनते हैं, ब्रीफकेस नहीं, बल्कि झोला लेकर चलते हैं, ये सादगी पसंद लोग कुर्ता-पायजामा पहनते हैं और उनके कपड़े सामान्य और औसत दर्जे के होते हैं।

इन्हीं मानदंडों के आधार पर उनकी टीम का चयन हुआ है, और यही लोग राहुल गांधी की ''नई कांग्रेस'' के चेहरा, आंखें और कान माने जा रहे हैं, जिसे राहुल संवारने की कोशिश कर रहे हैं।

इनमें से कई अब तक पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एआईसीसी की संरचना में प्रभावशाली पदों पर बैठा दिया गया है और वे उन राज्यों में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, जहां कांग्रेस सत्ता में है या जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं।

इनमें से कई राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनके चुनावी नतीजे कांग्रेस के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने निर्णय ले लिया है, और जब उन्होंने फैसला कर लिया तो किसी तरह की असहमति की कोई जगह नहीं रह जाती।

- राहुल की कोर टीम के सदस्यों के लिए, कांग्रेस का पुराना सिद्धांत, कि एक व्यक्ति, एक ही पद पा सकता है, भी लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, कृष्णा अल्लूवेरा, बिहार के प्रभारी हैं तथा साथ में वे यूथ कांग्रेस के भी इंचार्ज हैं।
- राहुल की कोर टीम पर, ऐसे कई परंपरा व कानून कायदे लागू नहीं होते, जो साधारण तौर पर सभी नेताओं पर लागू होते आये हैं। यह अलग बात है कि कोर टीम के सदस्यों ने अभी तक कोई भी चमत्कारिक लाभ नहीं दिलवाया है, कांग्रेस पार्टी को। बल्कि, जहाँ-जहाँ ये लोग सक्रिय हुए, कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार घटता ही जा रहा है, उनकी कहीं भी जवाबदेही नहीं पूछी जा रही है।

यह टीम केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में काम कर रही है और इसमें माणिकम टैगोर, मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा अल्लूवेरा, सचिन राव, हरीश चौधरी और भंवर जितेन्द्र सिंह शामिल हैं।

इन्हें लगातार प्रमोट किया जाता रहा है और विभिन्न राज्यों में प्रमुख जिम्मेवारी दी गई हैं, और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटियों में जगह दी गई है, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा है, क्योंकि पार्टी प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। बावजूद इसके, इन्होंने यह ज़रूर सुनिश्चित किया है कि वे सुर्खियों में बने रहें।

इनमें से अधिकांश नेताओं का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, लेकिन राहुल गांधी का इन पर विश्वास अब भी अडिग है।

एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में रही है या सत्ता में है, वहां लोक निर्माण विभाग मंत्री और राजस्व मंत्री ऐसे लोग हैं, जो राहुल गांधी या उनके करीबी समूह से जुड़े हुए हैं।

उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में गहलोत सरकार में हरीश चौधरी राजस्व मंत्री थे। विजय सिंगला, जो अब कांग्रेस के संयुक्त कोषाध्यक्ष हैं और पार्टी की संपत्तियों के प्रभारी हैं, पंजाब की कांग्रेस सरकार में सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। वहीं, बायरगौड़ा भी राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं, और वे कर्नाटक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

21 जुलाई से शुरु होगा संसद का मानसून सत्र

नई दिल्ली, 02 जुलाई। भारतीय संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। यह 21 अगस्त तक चलेगा। संसद के मानसून सत्र से जुड़े प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इस बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी।

मालूम हो कि मानसून सत्र में 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। मानसून सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीते दिनों एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार ने

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र शुरु करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सत्र 21 अगस्त तक चलेगा।

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी मुद्दों पर, संसद के नियमों के तहत, चर्चा के लिए तैयार है। तीन महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को शुरू होंगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

'नास्तिक साम्यवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है तिब्बतियों के धार्मिक गुरु का चयन करने का

दलाई लामा ने पुरजोर शब्दों में कहा कि वे और उनका ट्रस्ट, ''गाडेन फोड्रांग ट्रस्ट'' ही नये दलाई लामा का मनोनयन करेंगे

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2, जुलाई। तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा ने घोषणा की है कि वे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेंगे, और अगला दलाई लामा केवल गदेन फोड्रंग ट्रस्ट द्वारा ही नामित किया जाएगा-जो इस कार्य के लिए पृथ्वी पर एकमात्र अधिकृत संस्था है।

धर्मशाला से आई दलाई लामा की इस घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है और यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के लिए बड़ी असहजता का कारण बन गई है, जो तिब्बती जनता पर पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण का दावा करती रही है।

दलाई लामा को पूरी दुनिया में शांति के दूत और क्रूर चीनी शासन के विरुद्ध तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में गहरा सम्मान प्राप्त है। उन्हें इस संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

गाडेन फोड्रंग ट्रस्ट, दलाई लामा की निर्वासित तिब्बती सरकार के भारत के धर्मशाला से संचालित होता है और तिब्बती बौद्ध परंपरा के वरिष्ठतम लामाओं का एक समूह है।

- कुछ समय पूर्व दलाई लामा ने तिब्बत के दूर-दराज गाँव के पाँच साल के बच्चे को दलाई लामा का नया अवतार घोषित किया था, पर, घोषणा होते ही चीन की सरकार ने उस लड़के का अपहरण कर लिया और उसके बाद उस लड़के का नामो-निशान नहीं मिला था।
- इस घटना के बाद, दलाई लामा ने घोषणा की थी कि दलाई लामा का नया अवतार ''फ्री वर्ल्ड'' (गैर-साम्यवादी) देश में होगा, पर, कहाँ और कब यह बाद में सार्वजनिक किया जायेगा।
- दलाई लामा ने इसी संदर्भ में कहा था कि नये दलाई लामा के मनोनयन की प्रक्रिया का ''रिव्यु'' करेंगे तथा नया दलाई लामा उनके 90वें जन्मदिन के दिनों में मनोनीत कर दिया जायेगा।
- और, अब जब उनके 90वें जन्म दिन के उत्सव की तैयारियाँ शुरु हो गई है, गत रविवार से, दलाई लामा ने घोषणा की कि नये दलाई लामा का मनोनयन वो और उनकी समिति उसी पद्धति से करेगी, जो अतीत काल से चली आ रही है।

यह घोषणा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अगले दलाई लामा पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास को निषिद्ध करता है। यह न केवल वर्तमान दलाई लामा की वैधता को बरकरार रखता है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी रिज़र्वेशन लागू होगा

15 प्रतिशत आरक्षण एससी तथा 7.5 प्रतिशत एसटी के लिए है जो पीए, सहायक लाइब्रेरियन, कोर्ट असिस्टैंट, कोर्ट अटैन्डैंट, चैम्बर अटैन्डैंट आदि पदों पर लागू होगा

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 जुलाई। देश के इतिहास में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण लागू किया है। यह कदम मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के कार्यकाल में उठाया गया है, जो स्वयं अनुसूचित जाति से आते हैं।

24 जून को जारी एक सर्कुलर में बताया गया कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर 23 जून 2025 से प्रभाव में आ गया है।

167 पृष्ठों का दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स (सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 1961 के नियम 4ए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 1997 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, तैयार किये गये 200-बिंदु वाले आरक्षण ढांचे को दर्शाता है।

- इस रिज़र्वेशन का रोस्टर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने विस्तृत रूप से तैयार करवाया है तथा वे अपने कार्यकाल में लागू करा देना चाहते है।
- न्यायाधीश गवई स्वयम् भी एससी कैटेगरी में आते हैं तथा उन्होंने 167 पेज का यह विस्तृत रिज़र्वेशन दस्तावेज तैयार करवाया है, जो 24 जून को घोषित हुआ था तथा इस वर्ष 23 जून से इसे लागू माना जायेगा।

आरक्षण अनुपातः

15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए रखा गया है। तथा इस प्रकार हर 200 स्वीकृत पदों में 30 पद एस सी और 15 पद एसटी के लिए आरक्षित होंगे।

यह आरक्षण ढांचा सुप्रीम कोर्ट के कई प्रशासनिक पदों पर लागू होगा। प्रत्येक पद के लिए एक सीरियल नंबर आधारित सूची तैयार की गई है, जो बताती है कि स्वीकृत पदों की संख्या में कौन-से क्रम पर एस सी, एस टी के पद होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिया ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग से मिले

नई दिल्ली, 02 जुलाई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोग के साथ बैठक की और विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। कांग्रेस, राजद, माकपा, भाकपा, भाकपा (माले), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और समाजवादी पार्टी

- इन नेताओं ने बिहार में मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण पर आपत्ति जताई।

सहित 11 दलों के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्तों से मुलाकात की।

इन नेताओं ने आपत्ति जताई कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले मतदाता सूची की इस तरह की विशेष जांच कराना उचित नहीं है। यह प्रक्रिया पहले ही बिहार में शुरू हो चुकी है और अगले साल जिन पांच और राज्यों, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां भी इसे लागू किया जाना है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरएसएस व मोदी-शाह द्वय के बीच तनाव दिख रहा है, नये प्रदेशाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पर

मोदी-शाह का तर्क है कि यह नियुक्ति रूटीन (साधारण) संगठनात्मक प्रक्रिया है। पर, आरएसएस की शिकायत है, संघ परिवार में नियुक्तियाँ बातचीत व उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के बाद होती हैं, इस बार ऐसा नहीं हुआ

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जुलाई। संघ परिवार के भीतर एक नई खींचतान उभरती दिख रही है, क्योंकि कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शीर्ष नेतृत्व ने नए प्रदेश भाजपा अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी पर असंतोष जताया है। यह विवाद ऐसे संवेदनशील समय पर सामने आया है, जब प्रधानमंत्री मोदी, पांच देशों के कूटनीतिक दौरे पर हैं, जो बुधवार से ही शुरु हुआ है।

असामान्य तेज़ी दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महज़ दो दिनों में 14 नए राज्य अध्यक्षों की घोषणा कर दी, जिससे कई वरिष्ठ संघ पदाधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। जहाँ भाजपा नेता इस फेरबदल को सामान्य संगठनात्मक मजबूती का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं संघ के सूत्रों का कहना है कि इस प्रक्रिया में संघ से पारंपरिक सलाह-मशविरा नहीं किया गया, जिससे मतभेद और गहराए हैं।

- प्र.मंत्री मोदी, प्रांत प्रचारकों की बैठक में भी उपस्थित नहीं हो पायेंगे, विदेश यात्रा के कारण। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस बैठक में बाकी एजेण्डा के अलावा काफी खुली चर्चा होनी थी, संघ व भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के बीच बढ़ रहे तनाव पर।
- संघ के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि तनाव केवल तार्किक नहीं है। भाजपा का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आरएसएस व मोदी-शाह नेतृत्व, संघ परिवार के उभरते तूफान के बीच कैसे पार्टी व संघ की नैया, होशियारी से खे कर निकालते हैं।

संघ की तीन दिवसीय अहम् प्रांत प्रचारक बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में मोदी की गैरमौजूदगी ने तनाव को और बढ़ाया है। हालांकि, अधिकारिक रूप से यह बैठक शताब्दी समारोहों और राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए बुलाई गई है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)